आयकर विभाग

बजट 2025
बेहतर कल के लिए

सशक्त मध्यम वर्ग

- ₹12 लाख तक की सालाना आय पर और वेतनभोगी करदाताओ के लिए ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा (वेतनभोगियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती सहित)
- करदाता अब बिना किसी शर्त के अपने स्वामित्व वाली दो संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा कर सकते हैं
- सम्बंधित मूल्यांकन वर्ष के खत्म होने के बाद अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है
- राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से 29 अगस्त, 2024 या उसके बाद जमा की गई धनराशि को निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
- NPS वात्सल्य योगदान पर NPS खाते के समान टैक्स का लाभ मिलेगा

अनुपालन बोझ को कम करना

छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष से बढ़कर 10 वर्ष कर दी गई है

TDS/TCS नियमों में राहत

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर अब ₹1 लाख कर दी गई है
- किराए पर TDS की वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा
- RBI की लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम(LRS) के तहत भेजे हुए धन पर TCS कटौती की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई है
- विदेश में शिक्षा के लिए धन भेजने पर TCS नहीं लगेगा
- अगर तिमाही TCS विवरण भरने की आखिरी तारीख तक या उससे पहले TCS चुका दिया जाता है, तो देरी के लिए कोई मुकदमा नहीं चलेगा
- उच्च TDS कटौती केवल गैर-पैन मामलों में लागू होगी

रोजगार और निवेश को बढ़ावा

- देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्देशीय जहाज अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों के लिए टनेज कर योजना का विस्तार किया गया है
- स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, धारा 80-IAC के तहत लाभ को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। यह विस्तार 1 अप्रैल, 2030 से पहले शामिल किए गए योग्य स्टार्टअप्स को लाभ उपलब्ध कराएगा
- इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में निवेश की समय सीमा बढ़ा दी है
- IFSC में स्थापित वैश्विक कंपनियों की शिप-लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशेष लाभ प्रदान किए गए हैं
- लाभों का दावा करने के लिए, IFSC में काम शुरू करने की अंतिम तिथि को भी 5 साल बढ़ाकर 31.3.2030 कर दिया गया है
- इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश करने वाली श्रेणी I और श्रेणी II AIF को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभ पर कराधान की निश्चितता प्रदान की गई है

बढ़ता व्यापार

- सुगम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 3 वर्षीय ट्रांसफर प्राइसिंग ब्लॉक अवधि उपलब्ध होगी
- विस्तारित सेफ हार्बर नियमों से अंतर्राष्ट्रीय कराधान में मुकदमेबाजी कम होगी और निश्चितता बढ़ेगी
- इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में लगी निवासी कंपनी को सेवाएं या टेक्नोलॉजी प्रदान करने में लगे गैर-निवासियों के लिए प्रेसमटिव टैक्सेशन की व्यवस्था शुरू की गई है
- विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयों को आपूर्ति हेतु पुर्जे संग्रहीत करने वाले गैर-निवासियों के लिए नया सेफ हार्बर नियम बनाया गया है

वेबसाइट के लिए स्कैन करें

आयकर विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

FAQ के लिए स्कैन करें

CBC 15401/13/0017/2425

@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndia.Official @IncomeTaxIndiaOfficial @IncomeTaxIndiaOfficial www.incometax.gov.in